साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 39 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 17 मई 2023 से 23 मई 2023 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

दवा प्रतिरोधी मलेरिया का मुकाबला कर सकते हैं पारंपरिक औषधीय पौधे- शोध

नई दिल्ली। बौने लैब्राडोर चाय के पौधे की पत्तियों में एक ऐसा तेल होता है जो मलेरिया से लड़ने में मदद कर सकता है। आधुनिक चिकित्सा का अधिकांश भाग पारंपरिक, स्वदेशी प्रथाओं से उत्पन्न हुआ हैं। ये रीति-रिवाज आज भी जीवित हैं और वे कई तरह की बीमारियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। शोधकर्ताओं की एक टीम ने कनाडा के नुनाविक में उपयोग किए जाने वाले एक विशेष औषधीय लैब्राडोर चाय के पौधे की पत्तियों में यौगिकों की पहचान की है। उनमें से एक मलेरिया के परजीवी के खिलाफ मुकाबला करने की क्षमता रखता है।

लैब्राडोर चाय के कई, निकट संबंधी पौधे हैं जो सभी रोडोडेंड्रॉन वंश से संबंध रखते हैं। ये अजीब सी पत्तियों वाली छोटी, सदाबहार झाड़ियां हैं। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, आमतौर पर अमेरिका और कनाडा में स्वदेशी लोगों द्वारा इनका उपयोग हर्बल चाय बनाने के लिए किया जाता है। इनकी पत्तियों या जड़ों से बने पेय सर्दी या फ्लू, सिरदर्द या पेट में दर्द और कई अन्य बीमारियों के इलाज में मदद कर सकते हैं। पिछले अध्ययनों से पता चला है कि पौधों से निकाले गए आवश्यक तेलों में रोगाणुरोधी गुण होते हैं, जो एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी रोगाणुओं से लड़ने में मदद कर सकते हैं। बौना लैब्राडोर चाय, या रोडोडेंड्रोन सबआर्कटिकम, एक विशेष रूप से सुगंधित काढ़ा बनाने में काम आता है और सबआर्कटिक की कठोर परिस्थितियों में बढ़ता है। यह आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में अलास्का से साइबेरिया तक पाया जाता है। एक पारंपरिक दवा के रूप में इसके सामान्य उपयोग के बावजूद, इसकी रासायनिक संरचना और संभावित रोगाणुरोधी अनुप्रयोगों का अपेक्षाकृत अध्ययन नहीं किया गया है। इसलिए, नॉरमैंड वोयर और सहकर्मी पहली बार आर. सबआर्कटिकम के बारे में जानना चाहते थे और इसकी एंटीपैरासिटिक गतिविधि का परीक्षण करना चाहते थे। टीम ने उत्तरी क्यूबेक के एक क्षेत्र नुनाविक से आर. सबआर्कटिकम के पत्तों को इकट्ठा किया। शोधकर्ताओं ने 53 यौगिकों की पहचान करने के लिए पत्तियों से आवश्यक तेल निकाला और गैस क्रोमैटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्शन के साथ इसका विश्लेषण किया। इससे यह पता चला है कि 64.7 फीसदी तेल में एस्केरिडोल शामिल था, इसके बाद पी-सीमेन 21.1 फीसदी था। यौगिकों के इस मिश्रण को पहले निकट से संबंधित उत्तरी अमेरिकी लैब्राडोर चाय की किस्मों में दर्ज नहीं किया गया है, हालांकि यह यूरोप और एशिया में होने वाली उप-प्रजातियों में पाया गया है। यह देखने के लिए कि क्या इस आवश्यक तेल में मलेरिया-रोधी गुण थे, टीम ने प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, मलेरिया पैदा करने वाले परजीवी के दो वेरिएंट को तेल या सिर्फ एस्केरिडोल में डाला। प्रयोग में, इनमें से एक नस्ल मलेरिया-रोधी दवाओं के लिए प्रतिरोधी थी। आंकड़ों ने दिखाया कि एस्केरिडोल मुख्य रूप से वह चीज थी जो परजीवी के दोनों वैरिएंटों के खिलाफ काम करता था, जो अन्य, एंटीपैरासिटिक पारंपरिक दवाओं के साथ भी असरदार है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह काम पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल होने वाले पौधों की जांच और सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है, खासतौर पर उस जलवायु से जिसमें आए बदलाव ने इसे और कठोर बना दिया है। यह शोध एसीएस ओमेगा में प्रकाशित हुआ है।

साभार - डाउन टू अर्थ

अवुलापल्ली जलाशय पर्यावरण मंजूरी- Andhra Pradesh ने NGT के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

हैदराबाद। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 मई को सुनवाई करने पर सहमति जताई। एनजीटी ने राज्य के अवुलापल्ली जलाशय को मिली पर्यावरण मंजूरी को खारिज कर दिया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने मामले को सूचीबद्ध किया। पीठ ने कहा,'' यह लोक परियोजना है इसलिए हम इसे परसों के लिए सूचीबद्ध करते हैं।'' रोहतगी ने कहा कि यह एक असाधारण मामला है जहां हरित अधिकरण ने जलाशय को मिली पर्यावरण मंजूरी को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि हरित अधिकरण ने अवुलापल्ली जलाशय के निर्माण के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से मिली पर्यावरण मंजूरी को 11 मई को खारिज कर दिया था। हरित अधिकरण ने इस मंजूरी की वैधता को चुनौती देने वाली किसानों की याचिका पर यह फैसला सुनाया था। इसके अलावा एनजीटी ने आंध्र प्रदेश सरकार पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जो तीन माह के भीतर कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को दिया जाना था।

उद्योगों की मनमानी, फ्लाई ऐश डंपिंग पर पर्यावरण मित्र ने लिखा पत्र

रायगढ़ । पर्यावरण मित्र शहर में फ्लाई ऐश डस्ट से काली होती जन जीवन को लेकर रायगढ़ कलेक्टर, पर्यावरण विभाग सहित सचिव पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली सहित संबंधित तमाम अधिकारियों को प्रेषित किया है। पर्यावरण मित्र के द्वारा शहर से 20 किमी के दायरे में स्थापित शिव शक्ति प्रा लि, मां मंगला स्टील और शाकम्बरी स्टील प्रा लि के खिलाफ दस्तावेजी अध्ययन उपरांत नियमों की अनदेखी कर जल जंगल जीवन पर पड़ते विपरीत प्रभाव को लेकर शिकायत कर कड़ी करवाई की मांग की गई है।

20 किमी के दायरे में स्थापित शिव शक्ति प्रा लि, मां मंगला स्टील और शाकम्बरी स्टील प्रा लि के द्वारा चारो दिशाओं में स्थित गांव से लेकर शहरी क्षेत्र तक में उद्योगों के फ्लाई ऐश डस्ट उड़कर

घरों में पहुंच रहे है इससे वर्तमान में अनेक बीमारियां फैल रही हैं जिसमे खुजली दमा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां जन्म ले रही है। रायगढ़ शहर से 20 किमी के दायरे में स्थापित शिव शक्ति प्रा लि, मां मंगला स्टील और शाकम्बरी स्टील प्रा लि स्थापित हैं इनके द्वारा पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। यहां तक शहर के 48 वार्ड है जिसमे से कोई भी अछूता नहीं है ऐसा कोई घर नहीं बचा है जहां इन उद्योगों की काली राख घरों तक नहीं पहुंच रही है। पत्र में पर्यावरण मित्र के बजरंग अग्रवाल ने लिखा है की घर में बिना चप्पल के चलने पर पूरे तलवे काले हो जाते हैं। पेड़ पौधे काले हो चुके हैं पूरे शहर में फ्लाई ऐश की बारिश हो रही है। रायगढ़ वासी इन उद्योगों के धुएं और फ्लाई ऐश डस्ट की वजह से परेशान है। उद्योगों द्वारा लापरवाही पूर्वक फैलाए जा रहे प्रदूषण पर पर्यावरण विभाग का एक प्रतिशत भी ध्यान नहीं है। ईआइए रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है की 33 प्रतिशत जमीन पर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना है लेकिन इन उद्योगों द्वारा ग्रीन बेल्ट का विकास सिर्फ कागजों पर दिखाया गया है। ग्रीन बेल्ट की जांच एक टीम बनाकर कराए जाने की मांग की गई है। इतना ही नहीं इन उद्योगों द्वारा बोर का उपयोग का अवैध तरीके से भूजल का दोहन कर रहे जहां न तो पानी के उपयोग को लेकर कोई मीटर लगाया गया है। इससे सरकार को जलकर के रूप में मिलने वाली लाखो रु की टैक्स की भी चोरी की जा रही है। उद्योगों द्वारा महज 5 प्रतिशत जमीन पर चंद पेड़ लगाकर ग्रीन बेल्ट बता रहे है। इसकी भी समुचित जांच होनी चाहिए। उद्योगों के द्वारा फ्लाई ऐश और स्लैग का निस्तारण सीमेंट प्लांट, ईट भट्ठे, सड़क बनाने में खपत करना बताया जाता है जबकि उद्योगों द्वारा लाखो टन फ्लाई ऐश रातों रात गांव में डंप कर दिया जाता है। फ्लाई ऐश सीमेंट फैक्ट्री ईट भट्ठों सड़क बनाने में दिया जाना बताया जाता तो उसकी भी उद्योगों के खाते की जांच की जाए कब कब और किनको किनको दिया गया। उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की मॉनिटरिंग के लिए ऑन लाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं लगाया गया है जहां लगाया गया भी है तो उसमे छेड़खानी की जाती है। इन तमाम बिंदुओं पर जांच किया जाए और जांच में सही पाए जाने पर इन उद्योगों में तालाबंदी की जाए और भारी भरकम जुर्माना लगाया जाए जिसे जल जंगल और जमीन सुरक्षित हो सके।

हर 20 से 50 सवालों के जवाब ढूंढने में आधा लीटर पानी 'पी' जाता है चैट जीपीटी!

आप सभी ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित प्रोग्राम बड़ी तेजी से दुनिया भर में लोकप्रिय बन गया है। यह सही है कि इस तरह के प्रोग्रामों ने काफी हद तक हमारा जीवन आसान किया है, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित प्रोग्राम पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी काफी महंगे हैं, जो उसपर व्यापक प्रभाव डाल रहे हैं।

उदाहरण के लिए चैट जीपीटी की बात करें तो यह प्रोग्राम 20 से 50 सवालों के जवाब ढूंढने में करीब आधा लीटर पानी खर्च कर देता है। ऐसे में यह जल स्रोतों पर कितना ज्यादा दबाव डाल रहा है उसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित बॉट है, जिसकी फुल फॉर्म चैट जेनरेटिव प्रिंटेड ट्रांसफार्मर है। चैट जीपीटी गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन है, जो पूर्णत: एआई पर निर्भर करता है। मतलब, यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो बस टाइप कीजिए यह तुरंत आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख कर आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, रिवरसाइड के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पहली बार आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदद से चलने वाले इन प्रोग्रामों द्वारा की जा रही पानी की खपत का अध्ययन किया है। यह प्रोग्राम प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए बेहद बड़े आकार के डेटा प्रोसेसिंग सेंटर और उनमें रखे विशालकाय सर्वरों पर निर्भर करते हैं। जो सूचनाओं का आदान प्रदान और विश्लेषण करने के लिए क्लाउड कम्प्यूटेशंस पर भरोसा करते हैं। यदि केवल अमेरिका में मौजूद गूगल के डेटा केंद्रों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो इन्होने 2021 में अपने सर्वरों को ठंडा रखने के लिए करीब 1,270 करोड़ लीटर ताजे पानी की खपत की थी। आज जब दुनिया भर के लिए पानी दुर्लभ होता जा रहा है। सूखा और जलवायु परिवर्तन इससे जुड़ी समस्याओं को और विकराल बना रहे हैं। ऊपर से यह प्रोग्राम बड़े पैमाने पर इन जल स्रोतों पर दबाव् डाल रहे हैं, जोकि चिंता का विषय है। इस बारे में अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर शोलेई रेन ने बताया कि यह डेटा प्रोसेसिंग सेंटर दो तरह से बड़े पैमाने पर पानी की खपत करते हैं। सबसे पहला यह सेंटर बड़े पैमाने पर बिजली संयंत्रों से बिजली लेते हैं जो अपने आप को ठंडा रखने के लिए कूलिंग टावरों का उपयोग करते हैं। इसके लिए वो बड़े पैमाने पर पानी की खपत करते हैं। दूसरा इन डेटा केंद्रों में हजारों सर्वरों को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है। यह कूलिंग टावर ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं। इस बारे में रेन का कहना है कि इन कूलिंग टावरों में पानी का उपयोग किया जाता है जो भाप बनकर इन सेंटरों से निकली गर्मी को वातावरण से हटा देता है। उनके मुताबिक एआई के लिए बड़े पैमाने पर पानी की खपत को इसलिए भी ध्यान में रखा जाना और नियंत्रित करना जरूरी है क्योंकिं आने वाले समय में डेटा प्रोसेसिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो कहीं ज्यादा पानी का उपभोग करेगी। इसका उदाहरण देते हुई रिसर्च में कहा है कि अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के अत्याधुनिक डेटा केंद्रों में जीपीटी-3 एआई प्रोग्राम के लिए करीब दो सप्ताह में सात लाख लीटर पानी की खपत की गई जो करीब 370 बीएमडब्ल्यू कारों के निर्माण में होने वाली पानी की खपत के बराबर है। वहीं यदि एशिया में इन डेटा केन्दों को देखें जो अमेरिका की तुलना में कम दक्ष हैं वहां इसके लिए पानी की खपत तीन गुणा बढ़ जाएगी। ऐसे में वैज्ञानिकों के मुताबिक यह जरूरी है कि एआई मॉडल अपनी सामाजिक जिम्मदारी को समझने और अपने स्वयं के वाटर फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रयास करें, जिससे बढ़ते जल संकट की समस्या का सामना करने में यह मॉडल एक उदाहरण प्रस्तुत करें।

पर्यावरण संकट से मुक्ति, सीड बाल से लौटेगी हरियाली

बिलासपुर पौधरोपण की तैयारी कर रहीं संस्थाओं के लिए खुशखबरी। एक नई विधा पहुंचने को तैयार है, जो नर्सरी और गड्ढों पर होने वाले खर्च से छुटकारा दिलाएगा। नाम है सीड बाल। जिसकी मदद से पौधरोपण का काम बेहद आसान होगा।मानसून करीब आ रहा है। इसी के साथ पौधरोपण की तैयारियां जोर पकड़ने लगीं हैं। यदि नई विधि अपनाई गई तो, इस बार पौधरोपण का लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सकेगा बल्कि इस पर होने वाली भारी भरकम खर्च की राशि में कमी भी लाई जा सकेगी। सीड बाल की पहुंच और स्वीकार्यता के बाद बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने में भी मदद मिलेगी।

जगह, यह रखे जाएं,जहां पौधरोपण किया जाना है। बाद के सारे काम प्रकृति करेगी। अंकुरण के बाद सुरक्षित करने का काम अवश्य करें ताकि इनकी वृद्धि को बल मिल सके।

क्या है सीड बाल

खेत की मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट खाद और चयनित प्रजाति के पेड़ों के बीज के मात्र दो दाने, इन तीनों को मिलाकर हल्की नमी देने के बाद बॉल याने गेंद का रूप देना होगा। अनुकूल मौसम देख कर उस जगह, यह रखे जाएं,जहां पौधरोपण किया जाना है। बाद के सारे काम प्रकृति करेगी। अंकुरण के बाद सुरक्षित करने का काम अवश्य करें ताकि इनकी वृद्धि को बल मिल सके।

इसकी आवश्यकता क्यों

सीड बाल की विधि विकसित करने के पीछे जो सोच है, वह यह कि हर साल पौधरोपण का लक्ष्य तो होता है लेकिन पूरे नहीं हो पाते। कभी मौसम बाधा बनती है, तो कभी पौधों की चाही गई मात्रा का नहीं मिलना समस्या बनती है। इसके अलावा भारी भरकम खर्च भी तीसरी वजह है। इन तीनों कारणों को देखते हुए सीड बॉल को सभी समस्या का हल माना गया है।

यह होता है लाभ

सवाल उठाया जा सकता है कि बीज कहां से मिलेंगे? जवाब यह दिया जा रहा है कि रोड साइड के पेड़ों से गिरने वाले बीज एकत्र किए जा सकते हैं। इनमें सहज उपलब्धता वाले नीम, आंवला, जामुन, हर्रा, बहेड़ा, साल, इमली, सरई, आम, मुनगा और गंगा इमली मुख्य हैं। बता दें कि पौधरोपण में पीपल और बरगद के बाद इन्हीं प्रजातियों के पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती रही है।वर्जनहम सभी जानते हैं कि हमारे अस्तित्व और कल्याण के लिए पेड़ और पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं लेकिन हम में से कितने लोग नियमित रूप से पेड लगाते हैं? यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह समय है जब आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी प्रयास कर सके उन्हें करना चाहिए। सीड बॉल तकनीक निश्चित रूप से अपने आसपास हरियाली लाने में कारगर सिद्ध होगा।

मिशन लाइफ अभियानमिशन लाइफ पर्यावरण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

जैसलमेर महात्मा गांधी राजकीय स्कूल कनाना में सोमवार को मिशन लाइफ अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। सर्वप्रथम प्रार्थना सभा में मिशन लाइफ अभियान की संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद विद्यार्थियों, शिक्षकों व ग्रामीणों ने लाइफ स्टाइल फॉर एन्वायरनमेंट की शपथ ली।

संस्थान प्रधान करणसिंह राठौड़ ने बताया कि अभियान के तहत जागरुकता रैली, पर्यावरण संरक्षण संकल्प, शपथ, संवाद, घर-घर संपर्क सहित कार्यक्रम आयोजित हुए। सरपंच चैनकरणसिंह, एसएमसी अध्यक्ष प्रेमप्रकाश माली, संस्था प्रधान करणसिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना गया। इस दौरान छात्र-छात्राएं बैनर पोस्टर व हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए गांव के मुख्य रास्तों से गुजरते हुए पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया।

मध्य प्रदेश में तैयार होगी पर्यावरण संरक्षक युवा फौज, 2100 युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित

भोपाल । देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र से समृद्ध मध्य प्रदेश जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जूझते विश्व के लिए एक और शुभ प्रयास कर रहा है। लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फार एन्वायरमेंट (पर्यावरण फ्रेंडली जीवनशैली) में 2100 युवाओं को लाइफ वालंटियर के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

युवाओं को जागरूक करने के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यूथ फार लाइफ कार्यक्रम में प्रदेश के प्रत्येक जिले में लाइफ वालंटियर्स (स्वयंसेवी) का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी मिशन संबंधी मार्गदर्शिका के अनुसार सात विषय- ऊर्जा की बचत एवं नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग, जल की बचत एवं संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करना, घरेलू कचरे में कमी लाना (स्वच्छता संबंधी कार्य), स्वस्थ जीवन-शैली को अपनाना, सतत एवं शाश्वत भोजन पद्धति को बढ़ावा देना और ई-वेस्ट का उचित निष्पादन को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लास्गो में हुए %जलवायु परिवर्तन सम्मेलन% (काप-26) में पर्यावरण-संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जीवन-शैली में बदलाव के प्रमुख समाधानों के रूप में मिशन लाइफ का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की उपस्थिति में गुजरात के केवड़िया से मिशन लाइफ की ग्लोबल लांचिंग की गई। एप्को द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले से प्राप्त आवेदनों की जिलेवार सूची संबंधित जिला कलेक्टर को भेजी जाएगी। जिला कलेक्टर योग्य आवेदकों का चयन कर चयन सूची कार्यपालन संचालक, एप्को को भेजेंगे। आनलाइन आवेदनों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अपने जिले के ऐसे युवाओं, जो पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, को भी अपने स्व-विवेक से नामांकित कर सकेंगे। प्रत्येक जिले से अधिकतम 35 लाइफ वालंटियर चयनित किए जाएंगे। जिला स्तर पर चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यथासंभव शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र तथा महिला-पुरुष प्रतिभागियों का संतुलन बना रहे।

जिला गंगा समिति की बैठक-विश्व पर्यावरण दिवस पर जन आंदोलन व आउटरीच गतिविधियों को शुरू करने की बनाई गई योजना

बांका डीएम अंशुल कुमार की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में कई विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। गंगा समिति की बैठक में डीएम ने कई प्रस्ताव का अनुमोदन करने का साथ-साथ संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया।

जिसमें स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर ''मिशन लाईफ''अभियान के लिए बड़े पैमाने पर जन-अन्दोलन एवं आउटरीच गतिविधियों को शुरू करने की योजना का अनुमोदन किया गया। यह अभियान 03 मई से शुरू होकर 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समाप्त होगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत ''मिशन लाईफ''अभियान के सफल संचालन के लिए गंगा स्वच्छता संदेश रैली, पद यात्रा, नदियों के संरक्षण एवं स्वच्छता से संबंधित निबंध लेखन तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए डीडीसी कौशलेन्द्र कुमार एवं निदेशक, डीआरडीए बांका को निदेश दिया गया। स्वच्छ गंगा के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान, गतिविधियों को आयोजित करने के लिए जिला गंगा समिति को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। साथ ही उक्त गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रमों का फोटोग्राफ मेरी लाईफ पोर्टल पर अपलोड किये जाने का निर्देश दिया गया।

पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों को दिलाई शपथ

इटवा। सामाजिक वानिकी वन प्रभाग की तरफ से माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज इटवा में मिशन लाइफ कार्यक्रम के तहत कागज बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण को लेकर शपथ दिलाई गई।

विद्यालय के उप प्रधानाचार्य अशोक कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पर्यावरणीय हित में आवश्यकता अनुसार ही कागज का प्रयोग करें। कापियों में खाली पेज छोड़कर कागज की बर्बादी न करें। उन्होंने कहा कि धरती पर पर्यावरण संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। वगैर इसके संरक्षण के मानव जीवन सुखमय नहीं रह सकता है। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के छात्र व छात्राओ को पर्यावरण संरक्षण करने के लिये शपथ दिलाया। इस दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी अवधेश कुमार, वन दरोगा रिजवान अहमद, निखिल कुमार, शिक्षक सत्यानंद त्रिपाठी, धर्मेंद्र कुमार, श्याम नंदन शुक्ला, रामानंद त्रिपाठी, संजय चौधरी, अमरजीत, चंदे, सुधीर, ज्ञानदेव मौर्य, सत्यानंद त्रिपाठी ,रामशरण मौर्य ,दिलीप मौर्य, रविनंदन, सीपी सिंह मौजूद रहे।

दिल्ली में पर्यावरण में सुधार के लिए नियुक्त किए जाएंगे 3 एक्सपर्ट, इंटरव्यू के आधार पर होगा चयन

नई दिल्ली दिल्ली के पर्यावरण में सुधार के लिए अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) सेवानिवृत्त तकनीकी विशेषज्ञों की मदद लेगी। तीनों विशेषज्ञ केंद्र या राज्य सरकार से सेवानिवृत्त होंगे और दो साल के अनुबंध पर डीपीसीसी के लिए काम करेंगे। दो साल तक इनके काम के प्रदर्शन को देखते हुए ही इन्हें सेवा विस्तार दिया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक डीपीसीसी ने संयुक्त या अवर सचिव स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें से तीन अधिकारियों को तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। इन तीनों को वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक इन तकनीकी सलाहकारों की रिपोर्टिंग सीधे विशेष सचिव (पर्यावरण) अथवा डीपीसीसी के सदस्य सचिव को होगी। इन्हें शोध, मूल्यांकन, योजना, कौशल विकास, आंकड़ों की निगरानी अदालती मामलों में भी सहयोग करना होगा। साथ ही साथ यह तीनों सलाहकार नोट्स, मेमोरेंडम और दस्तावेज तैयार करने के अलावा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भी बनाएंगे। डीपीसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण से जंग में विभिन्न स्तरों पर काम किया जा रहा है। इसी दिशा में अब तकनीकी सलाहकारों की भी अनुबंध आधार पर नियुक्ति का फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार का प्रयास है कि बेहतर पर्यावरण के लिए पह पहलू पर काम करना होगा।

दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के लिए सुझाव और उपाय बताने होंगे, ताकि उनका प्रभाव राजधानी को प्रदूषित न करे। उन्होंने बताया कि इन सलाहकारों से 30 दिन में आवेदन करने के लिए कहा गया है। इसके बाद साक्षात्कार के आधार पर इनका चयन होगा और उम्मीद है कि दो से तीन माह में ये काम भी शुरू कर देंगे। बता दें कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली का वायु प्रदूषण लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। इसे लेकर सरकार और डीपीसीसी लगातार चिंता जता रहे हैं। इसके बाद अब पर्यावरण को सुधारने के लिए यह नई योजना तैयार की है। इससे राहत की उम्मीद है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008